

दैनिक

न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्व का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्व की टीम आपके घर विजित करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।



RNI NO - CHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, रविवार 13 जून 2021 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-03, अंक- 253

महत्वपूर्ण एवं खास

आतंकियों ने पुलिस और सीआरपीएफ की टीम को बनाया निशाना, 2 पुलिसकर्मी शहीद

श्रीनगर (आरएनएस)। जम्मू-कश्मीर में आतंकी हमले की घटना सामने आई है। यहां के सोपोर के आरामपोरा में नाका पर आतंकियों ने पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम पर हमला कर दिया है। इस हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए और 2 आम नागरिकों की मौत हो गई है। वहीं कई लोग घायल भी हुए हैं। सुरक्षाबलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों की तलाश की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार सोपोर के अरंपोरा में तैनात पुलिस और सीआरपीएफ की नाका पार्टी को निशाना बनाकर आतंकियों ने फायरिंग की। हमला करने के बाद आतंकी फरार हो गए। हमलावरों को पकड़ने के लिए इलाके की घेराबंदी कर बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इससे पहले शुक्रवार को शोपिया में लिटर अग्लर इलाके में तैनात पुलिस और सीआरपीएफ की नाका पार्टी को आतंकियों ने दूर से निशाना बनाकर कई राउंड फायरिंग की थी। इसके बाद आतंकी फरार हो गए। हालांकि इस हमले में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ था। आतंकी संगठन लगातार सुरक्षाबलों को निशाना बनाने की साजिशें रच रहे हैं।

कार पुलिसिया से टकराकर दो टुकड़ों में बंटी, तीन महिलाओं की मौत

छिंदवाड़ा (आरएनएस)। छिंदवाड़ा के रामकोना से एक शादी समारोह से लौट रही कार हादसे का शिकार होने के कारण दो टुकड़ों में बंट गई। हादसे के दौरान वाहन में सवार तीन महिलाओं की मौत पर ही दर्दनाक मौत हो गई जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को उपचार के लिए नागपुर रेफर कराया गया है। हादसा कितना भयानक था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पुलिसिया से टकराने के बाद कार के दो टुकड़े हो गए। पुलिस ने बताया कि सौसर निवासी सचिन जायसवाल अपने परिवार के साथ रामकोना में एक शादी समारोह में भाग लेकर घर लौट रहे थे, तभी नागपुर रोड स्थित ड्रीम होटल के पास उनकी कार के सामने एक बाइक सवार आ गया। बाइक सवार को बचाने के चक्र में कार चला रहे सचिन जायसवाल कार से नियंत्रण खो बैठे और कार सीधे पुलिसिया में जा टकराई और कार के दो टुकड़े हो गए। इस हादसे में कार में बैठी सौसर निवासी रोशनी पति अनूप जायसवाल, माधुरी पति आनंद जायसवाल और कलमेश्वर निवासी प्रिया पति सचिन जायसवाल की मौत पर ही मौत हो गई जबकि कार ड्राइव कर रहे सचिन जायसवाल और उनकी साथ बैठी नीलम जायसवाल बुरी तरह से घायल हो गए जिन्हें गंभीर हालत में नागपुर मेडिकल कालेज रेफर किया गया है।

दिल्ली के लाजपत नगर मार्केट में लगी भीषण आग

नई दिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली के लाजपत नगर मार्केट में स्थित एक शोरूम में आज भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 15 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर भेजी गई हैं। लाजपत नगर मार्केट के ब्लॉक-1 सेंट्रल मार्केट से भीषण आग लगने की सूचना मिली। दमकल विभाग से मिली जानकारी के अनुसार यहां के एक शोरूम में आग लगी हुई है। दमकल की 30 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया है। आगे की जानकारियों के मिलने का इंतजार किया जा रहा है। एक महीने के लॉकडाउन के बाद बाजार फिर से खुलने के बाद की यह पहली घटना है।

मेहुल चोकसी को फिर बड़ा झटका, डोमिनिका हाईकोर्ट ने नहीं दी जमानत

डोमिनिका। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का मुख्य आरोपी और डोमिनिका की जेल में बंद भगोड़े मेहुल चोकसी को बड़ा झटका लगा है। डोमिनिका हाईकोर्ट ने मेहुल चोकसी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने इस आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया क्योंकि उसके भागने का जोखिम है। जज वायनाटे एड्विन-रॉबर्ट्स ने चोकसी को 'फ्लाइंग रिस्क' वाला व्यक्ति माना। 'फ्लाइंग रिस्क' से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसके मुकदमे या जमानत की सुनवाई से पहले देश छोड़ने की संभावना हो। जमानत नहीं मिलने के बाद अब भगोड़े कारोबारी को जेल की सलाखों के पीछे दिन बताना पड़ेगा।

केंद्र द्वारा छत्तीसगढ़ को 1,909 करोड़ रुपये का अनुदान

» ताकि 'जल जीवन मिशन' के अंतर्गत हर घर को पहुंचे नल से जल
» राज्य में प्रत्येक ग्रामीण घर को 2023 तक नल से जल सुनिश्चित करने के लिए केंद्र का भारी प्रोत्साहन

नई दिल्ली (आरएनएस)। हर घर में नल से शुद्ध पेय जल पहुंचाने की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को 'जल जीवन मिशन' के अंतर्गत 2021-22 के लिए अनुदान की राशि बढ़ा कर 1,908.96 करोड़ रुपये कर दी है। पिछले वर्ष केन्द्रीय अनुदान की यह राशि 445.52 करोड़ रुपये थी। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए 453.71 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी भी कर दी है। केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री, गजेन्द्र सिंह शेखावत ने राज्य के आवंटन में चार गुना वृद्धि को मंजूरी प्रदान करते हुए छत्तीसगढ़ को भरोसा दिया है कि राज्य में प्रत्येक



ग्रामीण घर में 2023 तक नल से शुद्ध पेय जल पहुंचाने के लिए उसे हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। 2019 में 'जल जीवन मिशन' के शुभारंभ के समय देश में कुल मौजूद 19.20 करोड़ ग्रामीण घरों में से केवल 3.23 करोड़ घरों, यानि मात्र 17 प्रतिशत के यहाँ घरेलू नल कनेक्शन था। और, उसके बाद के 21 महीनों के दौरान - कोविड-19 महामारी की विभीषिका और उसके कारण लगे अनेक लॉकडाउन के बावजूद - 'जल जीवन मिशन' ने जोर उपलब्ध कराया जाए। आज देश से काम करते हुए सवा चार करोड़

नए घरों तक नल से शुद्ध जल पहुंचाया है। यानि इन 21 महीनों में 22 प्रतिशत प्रगति हासिल की गयी जिसके फलस्वरूप आज देश के ग्रामीण इलाकों के 7.50 करोड़ घरों में (अर्थात 39 प्रतिशत) पीने के साफ पानी की सपनाई नल से होने लग गयी है। गोवा, तेलंगाना, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और पुदुचेरी ने अपने यहाँ के सभी ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन पहुंचा कर 100 प्रतिशत कामयाबी हासिल कर ली है और वे 'हर घर जल' प्रदेश बन गए हैं। प्रधानमंत्री के 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' सिद्धान्त में अंतर्निहित मूल भावना के ही अनुरूप 'जल जीवन मिशन' का भी संकल्प है कि 'कोई भी छूटे ना' और हर गाँव के हर घर में नल से जल उपलब्ध कराया जाए। आज देश के 62 जिलों और 92 हजार से

ज्यादा गावों में हर घर में नल से पेय जल मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में 19,684 गावों में रह रहे कुल 45.48 लाख परिवारों में से केवल 5.69 लाख ग्रामीण परिवारों (12.51 प्रतिशत) को ही नल से जल की आपूर्ति हो पा रही है। 15 अगस्त 2019 को 'जल जीवन मिशन' के शुभारंभ के समय राज्य में 3.19 लाख ग्रामीण घरों (7.03 प्रतिशत) में ही नल जल कनेक्शन था। और, इन 21 महीनों के दौरान भी छत्तीसगढ़ में केवल 2.49 लाख (5.49 प्रतिशत) ग्रामीण घरों तक ही नए नल जल कनेक्शन पहुंचाए जा सके- जो धीमी गति के मामले में पूरे देश में दूसरे नंबर पर है। राज्य को 'हर घर जल' बनने के लिए अभी शेष 39.78 ग्रामीण घरों में नल जल कनेक्शन पहुंचाना बाकी है। छत्तीसगढ़ के 5,530 गावों में नल जल कनेक्शन देने के लिए तो अब तक जल आपूर्ति संबंधी कार्य भी शुरू नहीं हुए हैं। 'हर घर जल' बनने के लिए राज्य ने 2021-22 के दौरान

22.14 लाख घरों में नल जल कनेक्शन देने की योजना बनाई है, जबकि 2022-23 में 11.37 लाख घरों को तथा 2023-24 में शेष बचे 6.29 लाख घरों तक नल कनेक्शन से पीने का पानी पहुंचाया जाएगा। पिछले वित्त वर्ष के दौरान छत्तीसगढ़ 'जल जीवन मिशन' के तहत केवल 1.51 लाख नल जल कनेक्शन ही उपलब्ध करा पाया था। केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री, गजेन्द्र सिंह शेखावत ने इस सिलसिले में राज्य के मुख्य मंत्री को पत्र कर छत्तीसगढ़ से आग्रह किया है कि ग्रामीण घरों में नल जल कनेक्शन देने के काम में तेजी लायी जाए तथा इस दिशा में हर गाँव में कार्य शुरू कर दिया जाए ताकि राज्य 2023 तक 'हर घर जल' बन जाए। 2020-21 के दौरान छत्तीसगढ़ को 'जल जीवन मिशन' के तहत केन्द्रीय अनुदान के रूप में 445.52 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, लेकिन कार्यान्वयन की धीमी रफ्तार के कारण राज्य केवल 334.14 करोड़ रुपये ही आहतरित कर पाया, जिस कारण उसे गाँव-देहात की जल आपूर्ति जैसे जनसेवी कार्य के लिए दिए गए 111.48 करोड़ रुपये लौटाने पड़े। छत्तीसगढ़ के लिए केन्द्रीय आवंटन (1,908.96 करोड़ रुपये) में इस वित्त वर्ष में हुई इस चार गुना वृद्धि, पिछले वित्त वर्ष के अंत में खर्च न हो पाए 168.52 करोड़ रुपये की राशि और राज्य के समतुल्य अंश के रूप में दी गई राशि में 113.04 करोड़ रुपये की कमी वाली राशि के साथ मौजूदा वित्त वर्ष के लिए राज्य के समतुल्य अंश की राशि को जोड़ कर राज्य के पास 'जल जीवन मिशन' से जुड़े कार्यों के लिए 2021-22 में समग्र रूप से 4,268 रुपये पकड़े तौर पर उपलब्ध हैं। यानि, 'हर घर जल' के लिए धन की कोई कमी नहीं है। गजेन्द्र सिंह शेखावत ने उम्मीद जताई है कि छत्तीसगढ़ सरकार इस विशाल धनराशि का भरपूर उपयोग कर राज्य के प्रत्येक ग्रामीण घर में नल जल कनेक्शन सुनिश्चित कर पाएगी।

25 साल से ज्यादा पुराने सेना के रिकॉर्ड होंगे सार्वजनिक: राजनाथ

नई दिल्ली (आरएनएस)। रक्षा मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए युद्धों और अभियानों के इतिहास के संग्रह, संकलन, प्रकाशन और उन्हें सार्वजनिक करने की नीति को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को इस नीति को मंजूरी दी। इस नीति के तहत रक्षा मंत्रालय का प्रत्येक संगठन जैसे सेना, एकीकृत रक्षा स्टाफ, असफ राइफल्स और भारतीय तटरक्षक युद्ध डायरियों, कार्यवाही से संबंधित पत्रों, संचालन संबंधी रिकॉर्ड बुक और अन्य सभी रिकॉर्ड रक्षा मंत्रालय के इतिहास विभाग को भेजेंगे जिससे कि उन्हें संकलित और संग्रहित कर इतिहास लेखन के काम में इस्तेमाल किया जा सके। रिकॉर्ड को सार्वजनिक करने की जिम्मेदारी पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट 1993 और पब्लिक रिकॉर्ड रूल 1997 के तहत संबंधित संगठन की ही होगी। नयी

नीति के अनुसार सामान्य तौर पर रिकॉर्ड 25 वर्षों में सार्वजनिक किए जाने चाहिए। पच्चीस वर्षों से पुराने रिकॉर्ड युद्ध और अभियानों के इतिहास के संकलन तथा विशेषज्ञों को सूचना देने के बाद राष्ट्रीय अभिलेखागार में भेजे जाने चाहिए। युद्ध और अभियानों के संकलन, मंजूरी और प्रकाशन के समन्वय की जिम्मेदारी इतिहास विभाग की होगी। नीति में रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति के गठन का प्रावधान किया गया है जिसमें सेना, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के साथ साथ अन्य संगठनों के प्रतिनिधि और जरूरत पड़ने पर जाने माने सैन्य इतिहासकार शामिल होंगे जो इतिहास का संकलन करेंगे। इस समिति का गठन युद्ध के दो वर्ष के अंदर किया जाना होगा और इसे तीन वर्षों में रिकॉर्ड का संकलन उसे संबंधित पक्षों को भेजना होगा।

भारत में 24 घंटे में 84,332 नए मामले दर्ज किए गए

» यह संख्या 70 दिनों के बाद सबसे कम

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारत में दैनिक नये मामलों की संख्या में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में देश में 84,332 दैनिक नये मामले दर्ज किए गए। लगातार पांचवें दिन देश में कोविड-19 के नये मामलों की संख्या एक लाख से कम दर्ज की गयी। यह केंद्र और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के सहयोग से किए जा रहे प्रयासों का नतीजा है। भारत में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या



लगातार घट रही है। सक्रिय मामलों की संख्या गिरकर आज 10,80,690 हो गयी। लगातार 12वें दिन यह संख्या 20 लाख से कम है। पिछले 24 घंटे में सक्रिय मामलों की संख्या में कुल 40,981 की कमी आयी है। यह

अब देश के कुल कोविड पॉजिटिव मामलों का केवल 3.68 प्रतिशत है। साथ ही लगातार 30वें दिन भारत में बीमारी से स्वस्थ होने वाले लोगों की दैनिक संख्या कोविड-19 के दैनिक नए मामलों से ज्यादा है। पिछले 24 घंटे में बीमारी से 1,21,311 लोग स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटे में दैनिक नये मामलों की तुलना में बीमारी से 36,979 ज्यादा लोग स्वस्थ हुए हैं। भारत में महामारी के शुरू होने के बाद से पहले ही कुल 2,79,11,384 लोगों में कोविड-19 ठीक हो चुका है और पिछले 24 घंटे में बीमारी से कुल 1,21,311 लोग स्वस्थ हुए हैं। बीमारी से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर भी बेहतर होकर 95.07 प्रतिशत हो गयी है और इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। भारत में पिछले 24 घंटे में कुल 19,20,477 जांच हुई जिसके साथ अब तक हुए जांच की कुल संख्या 37.62 करोड़ से ज्यादा (37,62,32,162) है। जहां एक तरफ पूरे देश में कोविड की जांच बढ़ गयी है, वहीं दूसरी तरफ साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट भी लगातार घट रहा है।

देशभर में कृषि कानून के विरोध में 26 जून को राजभवनों पर किसानों का होगा प्रदर्शन

नई दिल्ली (आरएनएस)। कृषि कानून के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन को 197 दिन हो चुके हैं। किसानों ने आंदोलन को तेज करने पर विचार किया वहीं सरकार पर दबाव बनाने के लिए रणनीति बनाई। इसी बीच किसानों ने 26 जून को देशभर में राजभवनों पर धरना देने की घोषणा की। संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के नेताओं ने बताया कि, 26 जून के दिन किसानों का विरोध प्रदर्शन होगा और इस दौरान काले झंडे दिखाए जाएंगे। साथ ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ज्ञापन भेजेंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता धर्मेन्द्र मलिक ने आईएनएस को बताया कि, 26 जून को खेती बचाओ, लोकतंत्र बचाओ दिवस के रूप में मनाया जाएगा। वहीं राजभवनों पर काले झंडे दिखाकर और हर राज्यों में राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन देकर अपना विरोध दर्ज करायेंगे। किसान नेताओं ने अनुसार, 26 जून को ही पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लागू की थी। आज भी मोदी



सरकार ने भी देश में अघोषित इमरजेंसी लगा रखी है। दूसरी ओर किसानों ने बॉर्डर पर महिलाओं की सुरक्षा पर भी चिंता व्यक्त की। किसानों के मुताबिक आंदोलन स्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर शनिवार तक समिति गठित कर देगे। वहीं एक मोबाइल नंबर की महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेशा बांडा को कैथल में काले झंडों और नारों का सामना करना पड़ा। महिलाओं और पुरुष किसान दोनों ने बड़ी संख्या में अपना प्रतिरोध व्यक्त करने के लिए भीषण गर्मी का सामना किया। चरखी दादरी में

सावजनिक किया जाएगा। एसकेएम के अनुसार, किसान लगातार काले झंडे दिखा कर अलग-अलग जगहों पर बीजेपी नेताओं के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेशा बांडा को कैथल में काले झंडों और नारों का सामना करना पड़ा। महिलाओं और पुरुष किसान दोनों ने बड़ी संख्या में अपना प्रतिरोध व्यक्त करने के लिए भीषण गर्मी का सामना किया। चरखी दादरी में

मोदी सरकार ने दी बड़ी राहत: ब्लैक फंगस की दवा पर नहीं लगेगा जीएसटी

» एंजुलेंस समेत कई दवाइयों पर टैक्स की दर घटी

नई दिल्ली (आरएनएस)। आज जीएसटी काउंसिल की 44वीं बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जैसे कि कोविड संबंधी दवा, वैक्सीन और अन्य जरूरी वस्तुओं जैसे कि एंजुलेंस आदि पर जीएसटी की दर घटाने का अहम फैसला लिया गया। केंद्र सरकार ने इन सभी आवश्यक वस्तुओं पर लगने वाले जीएसटी कर की अलग-अलग दरों को जरूरत के आवश्यकता के अनुसार घटाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की बैठक में लिए

गए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि परिषद में टीके पर पांच फीसदी की दर को कायम रखने पर सहमति बनी है। इसके साथ ही एंजुलेंस पर जीएसटी की दर को 28 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी किया गया है। परिषद ने रेमेडिसविर पर कर की दर को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने को लेकर सहमति दी है। टोसिलिमैब, एम्पेटेरिसिन पर भी कोई कर नहीं लगेगा। सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद ने मेडिकल ग्रेड ऑक्सिजन, बीआईपीपी मशीनों, ऑक्सिजन कंसट्रेटर, वेंटिलेटर, पल्स ऑक्समीटर पर कर की दर को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया है।

कोविड-19 रोगियों पर कोल्किसिन दवा का क्लीनिकल ट्रायल करने के लिए विनियामक से मिली मंजूरी

नई दिल्ली (आरएनएस)। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) एवं लैक्सोई लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद, को भारतीय औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) द्वारा कोविड-19 रोगियों के उपचार के दौरान नैदानिक परिणामों में सुधार के लिए कोल्किसिन दवा की सुरक्षा और प्रभावकारिता का आकलन करने के लिए टू-आर्म फेज-2 क्लीनिकल ट्रायल करने के लिए विनियामकीय मंजूरी मिल गयी है। इस महत्वपूर्ण क्लीनिकल ट्रायल में सीएसआईआर-भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीटी), हैदराबाद और सीएसआईआर-भारतीय एकीकृत



चिकित्सा संस्थान (आईआईआईएम), जम्मू भागीदार है। सीएसआईआर के महानिदेशक डॉ. शेखर सी मांडे ने गठिया और संबंधित

सीएसआईआर महानिदेशक के सलाहकार डॉ. राम विश्वकर्मा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि स्वास्थ्य सेवा मानक के साथ संयोजन में कोल्किसिन हृदय संबंधी सह-रुग्णता वाले कोविड रोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण चिकित्सीय हस्तक्षेप होगा और साथ ही प्रिनफ्लेमेटरी साइटोकिन्स को कम करने में भी मददगार होगा, जिससे रोगियों की दशा में तेजी से सुधार होगा। कई वैश्विक अध्ययनों ने अब इस बात की पुष्टि की है कि कोविड-19 संक्रमण और पोस्ट-कोविड सिंड्रोम के दौरान हृदय संबंधी जटिलताओं से कई लोगों की जान चली जाती है और इसलिए नई दवाओं या नये उद्देश्य वाले दवाओं की तलाश करना आवश्यक है।

डॉ. एस चंद्रशेखर (निदेशक सीएसआईआर -आईआईसीटी, हैदराबाद) और डॉ. डीएस रेड्डी (निदेशक, सीएसआईआर-आईआईआईएम, जम्मू) और सीएसआईआर के दो सहयोगी संस्थानों ने कहा कि वे कोल्किसिन से जुड़े इस फेज-2 नैदानिक प्रभावकारिता परीक्षण के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिससे अस्पताल में भर्ती मरीजों के प्रबंधन में जीवन रक्षक हस्तक्षेप हो सकता है। भारत इस प्रमुख दवा के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है और अगर यह सफल रहा तो इसे मरीजों को सस्ती कीमत पर उपलब्ध कराया जाएगा। लैक्सोई के सीईओ डॉ. राम उपाध्याय ने बताया कि भारत भर में

कई साइटों पर मरीजों का नामांकन शुरू हो चुका है और अगले आठ से 10 हफ्तों में ट्रायल पूरा होने की संभावना है। उन्होंने आगे कहा कि इस ट्रायल के परिणामों और नियामकीय मंजूरी के आधार पर यह दवा भारत की बड़ी आबादी को उपलब्ध कराई जा सकती है। प्रमुख चिकित्सा पत्रिकाओं में हाल में प्रकाशित हुए नैदानिक अध्ययनों के अनुसार कोल्किसिन का दिल की सर्जरी और एड्रियल फाईब्रिलेशन एब्लेशन के बाद रिकरंट पेरीकार्डिटिस, पोस्ट-पेरीकार्डियोटॉमी सिंड्रोम और पेरी-प्रोसिनजरल एड्रियल फाईब्रिलेशन की दरों में होने वाली महत्वपूर्ण कमी से संबंध है।